



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2010/माघ 26, 1931

No. 48]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2010/MAGHA 26, 1931

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुडगाँव, 11 फरवरी, 2010

सं. जेईआरसी-9/2009.—गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी समर्थकारी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना

- (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण तथा वितरण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2009 है।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (iii) ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य तथा अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव, पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

- (ग) "विद्यमान कायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को पारेषण प्रणाली या वितरण नेटवर्क का उपयोक्ता है चाहे वह उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी हो;
- (घ) "नोडल अभिकरण" से इन विनियमों के विनियम 8 में परिभाषित नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;
- (ङ) "निर्बाध पहुंच उपयोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग या प्रदाय के अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से विद्युत का प्रदाय करने की अनुज्ञा दी है, तथा अभिव्यक्ति में ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित है जिसने निर्बाध पहुंच प्राप्त की है या प्राप्त करने का आशय रखता है;
- (च) "राज्य" से गांधी राज्य अभिप्रेत है और संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं; किन्तु दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित नहीं है।
- (2) इन विनियमों में आने वाले शब्दों तथा पदों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में है तथा इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु इसमें या अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, का वहीं अर्थ होगा जो साधारणतः विद्युत उद्योग में उनका है।

3. निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं का प्रवर्गीकरण

- (i) निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं को दो प्रवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :-
- (क) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता; और
- (ख) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता।
- (ii) पच्चीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान करने वाला या निर्बाध पहुंच लेने का आशय रखने वाला व्यक्ति दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता होगा :
- परंतु यह कि विद्यमान कायदाग्राही, यथास्थिति, पारेषण प्रणाली या वितरण नेटवर्क के दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता समझे जाएंगे।
- (iii) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता से भिन्न निर्बाध पहुंच उपयोक्ता अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता होंगे :

परंतु कि अनुज्ञात अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अधिकतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता अपनी अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनः आरक्षण प्राप्त के पात्र और पुनः पात्र होंगे।

4. विद्यमान फायदाग्राहियों के ब्यौरों का प्रकाशन

पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 180 दिनों के भीतर या तो अपनी वेबसाइट पर या राज्य भार प्रेषण केंद्र की वेबसाइट पर विद्यमान फायदाग्राहियों (जिसमें स्वयं-उपयोग तथा ऐसे विभाजित अभिकरणों द्वारा उपयोग भी सम्मिलित है जो पहले एकीकृत थे) के ब्यौरे प्रकाशित करेंगे।

5. दीर्घ-कालिक तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए मानदंड

(i) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच राज्य ग्रिड कोड में अनुबद्ध पारेषण योजना मानदंडों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच तब अनुज्ञात किया जाएगा, यदि निर्बाध पहुंच के लिए अनुरोध निम्नलिखित का उपयोग करते हुए किया गया हो : -

- (क) अंतर्निहित डिजाइन मार्जिन;
- (ख) ऊर्जा प्रवाहों में फेरफार के कारण उपलब्ध मार्जिन; और
- (ग) भावी भार वृद्धि का प्रबंध करने के लिए सृजित इन-बिल्ट अपर्याप्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन।

6. निर्बाध पहुंच के लिए भावी अनुरोध

पारेषण प्रणाली तथा वितरण नेटवर्क के उपयोग के लिए सभी भावी अनुरोधों को इन विनियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

7. दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता की आबंटन पूर्विकता

दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच की आबंटन पूर्विकता अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता की आरक्षण पूर्विकता से उच्चतर होगी :

परंतु यह कि प्रवर्ग में (दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता या अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता) निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं तथा एकीकृत इकाई द्वारा स्वयं-उपयोग के बीच कोई विभेद नहीं होगा।

8. नोडल अभिकरण

(i) राज्य के भीतर दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच की व्यवस्था के लिए नोडल अभिकरण राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) होगी।

- (ii) राज्य के भीतर अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए नोडल अभिकरण राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) होगा।

9. विस्तृत प्रक्रिया

नोडल अभिकरण इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिनों के भीतर विस्तृत प्रक्रिया, मार्गदर्शक सिद्धांत तथा प्ररूप जारी करेगा।

10. दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए प्रक्रिया

- (i) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन विनियम 9 के अधीन जारी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संबंधित नोडल अभिकरण को दिया जाएगा।
- (ii) आवेदन में आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण का स्थान, निकासी का स्थान, निर्बाध पहुंच लेने की अवधि, व्यस्ततम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे तथा ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो नोडल अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (iii) आवेदन के साथ पचास हजार रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी जो उस नाम तथा ऐसी रीति से संदेय होगी जो नोडल अभिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए।
- (iv) संबंधित अन्य अभिकरणों, जिसमें अन्य पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं, के परामर्श से नोडल अभिकरण द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन के आधार पर, नोडल अभिकरण, आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, आवेदक को इस बात की सूचना देगा कि क्या बिना किसी प्रणाली सुदृढीकरण के दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किया जा सकता है या नहीं।
- (v) यदि नोडल अभिकरण की राय में दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच देने से पूर्व और प्रणाली सुदृढीकरण आवश्यक है तो आवेदक नोडल अभिकरण से प्रणाली अध्ययन तथा प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लागत प्राक्कलन तथा अनुसूची पूरा करने के प्रयोजन के लिए प्रारंभिक अन्वेषण करने का अनुरोध कर सकेगा।
- (vi) नोडल अभिकरण उप-विनियम (v) के अधीन आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल अध्ययन करेगा तथा अध्ययनों के परिणामों के बारे में आवेदक को अनुरोध प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर देगा।

- (vii) आवेदक प्रणाली अध्ययन करने तथा प्रणाली सुदृढीकरण के लिए लागत प्राक्कलन तथा अनुसूची पूरा करने के प्रयोजन के लिए आरंभिक अध्ययन करने हेतु नोडल अभिकरण द्वारा उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

परंतु यह कि आवेदक द्वारा संदत्त पचास हजार रुपए की फीस को आवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले वास्तविक व्यय में समायोजित किया जाएगा।

11. थोक क्षमता करार

- (i) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उनकी पारेषण प्रणाली तथा वितरण नेटवर्क का उपयोग करने के लिए थोक ऊर्जा पारेषण/वितरण क्षमता करार करेगा।
- (ii) करार में अन्य बातों के साथ, किसी घटना के घटित होने पर उसको पर्यवसित करने तथा संविदा करने वाले पक्षकारों पर उसके परिणाम के बारे में उपबंध किया जाएगा।
- (iii) करार किए जाने तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र को प्रतियां देने के पश्चात्, राज्य भार प्रेषण केंद्र निर्बाध पहुंच उपयोक्ता को उस तारीख के बारे में सूचित करेगा जिस तारीख को निर्बाध पहुंच उपलब्ध होने की संभावना है :

परंतु यह कि निर्बाध पहुंच की उपलब्धता की तारीख करारों को प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिन अन्यून होगी।

12. विद्यमान विकल्प

- (i) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, थोक पारेषण/वितरण क्षमता करार के अधीन अपने अधिकारों तथा बाध्यताओं का परित्याग नहीं करेगा या उनका अंतरण नहीं करेगा।
- (ii) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता द्वारा अधिकारों तथा बाध्यताओं का परित्याग या अंतरण ऐसे प्रतिकर के संदाय के अधीन रहते हुए किया जाएगा जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

13. अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए प्रक्रिया

- (i) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता पारेषण/वितरण पहुंच के लिए आवेदन राज्य भार प्रेषण केंद्र को प्रस्तुत करेगा।

- (ii) आवेदन में आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण का स्थान, निकासी का स्थान, निर्बाध पहुंच लेने की अवधि, व्यस्ततम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे तथा ऐसे अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;
 - (iii) आवेदन के साथ पांच हजार रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी तथा किस नाम में तथा किसी रीति में संदेय होगी इसका विनिश्चय राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा किया जाएगा;
 - (iv) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच द्वारा आरक्षित क्षमता का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाएगा।
14. अल्प-कालिक उपयोक्ताओं के लिए क्षमता का आरक्षण
- (i) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता की दशा में, दिए गए स्थान पर, यदि आरक्षित चाही गई क्षमता उपलब्ध क्षमता से कम है तो प्रत्येक अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता विनियम 16 के अनुसार पारेषण या चक्रण प्रभारों का संदाय करेगा।
 - (ii) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच की दशा में, यदि समय स्थान पर निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं द्वारा आरक्षित चाही गई क्षमता उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो क्षमता के आरक्षण पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) संबंधित राज्य भार प्रेषण केंद्र/फैक्स/ई-मेल के माध्यम से स्नैप बोली आमंत्रित करेंगे,
 - (ख) बोली की न्यूनतम कीमत विनियम 16 के अनुसार अवधारित कीमत होगी।
 - (ग) बोलीकर्ता न्यूनतम कीमत से ऊपर प्रतिशतता स्थान के अनुसार कीमत कोट करेगा।
 - (घ) क्षमता का आरक्षण कोट की गई कीमत के नीचे के क्रमानुसार किया जाएगा।
 - (ङ) समान कीमत, यदि अपेक्षित हो, की दशा में (अर्थात् क्षमता कम होने के कारण), क्षमता का आरक्षण चाही गई क्षमता के अनुपात में होगा।
 - (च) ऐसे निर्बाध पहुंच उपयोक्ता, जो अपने द्वारा चाही गई क्षमता से कम क्षमता के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं, अपने द्वारा कोट की गई दर पर आबंटित क्षमता के लिए प्रभारों का संदाय करेंगे।

(छ) राज्य भार प्रेषण केंद्र, पैतालीस दिन के भीतर, अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं के लिए पारेषण तथा वितरण क्षमता, जिसमें बोली के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी है, के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा।

15. अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता द्वारा आरक्षित क्षमता का अनुपयोग

- (i) यदि अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता आरक्षित क्षमता का पूर्ण या सारवान् भाग का उपयोग करने में असमर्थ है, तो वह आरक्षित क्षमता के उपयोग करने में अपनी असमर्थता के कारणों के साथ राज्य भार प्रेषण केंद्र को सूचित करेगा तथा अपनी आरक्षण क्षमता को अभ्यर्पित करेगा।
- (ii) राज्य भार प्रेषण केंद्र अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता की आरक्षण क्षमता में कमी या उसको तब रद्द कर सकेगा जब ऐसा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता लगातार आरक्षण क्षमता का कम उपयोग करता है।
- (iii) ऐसा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता, जिसने उप-विनियम (i) के अधीन आरक्षित क्षमता को अभ्यर्पित किया है या जिसकी आरक्षण क्षमता को उप-विनियम (ii) के अधीन उसमें कमी या उसे रद्द की है, सात दिनों के लिए वा, यथास्थिति, आरक्षण या कमी या रद्द करने की अवधि, जो भी अवधि कम हो, मूल आरक्षित पारेषण क्षमता के आधार पर पारेषण/चक्रण प्रभारों तथा अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन प्रभार का वहन करेगा।
- (iv) उप-विनियम (i) या उप-विनियम (ii) के अधीन राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा आरक्षित क्षमता के अभ्यर्पण या कमी या रद्द करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षमता का आरक्षण इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता के लिए किया जाएगा।

16. निर्बाध पहुंच प्रभार

निर्बाध पहुंच के लिए प्रभारों में निम्नलिखित एक या अधिक संघटक सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारेषण/वितरण (चक्रण) प्रभार

अंतर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के सिवाय अंतःराज्यिक पारेषण या वितरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रभारों को निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) वार्षिक प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित टैरिफ के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा किया जाएगा तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं से समायोजनीय राजस्व में कटौती करने के पश्चात् इन प्रभारों को अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं द्वारा बांटा जाएगा।

- (ii) (क) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता द्वारा संदेय प्रभारों की संगणना निम्नलिखित पद्धति के अनुसार की जाएगी :

$$\text{एसटी दर} = 0.25 \times [\text{टीएससी/एवी सीएपी}] / 365$$

जहां, एसटी दर अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता के लिए प्रतिदिन प्रति मेगावाट रुपए में दर है।

“टीएससी” से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण/वितरण प्रभार अभिप्रेत हैं।

“एवी सीएपी” से प्रणाली द्वारा दी गई मेगावाट में औसत क्षमता अभिप्रेत है।

पूर्व वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता पारेषण प्रणाली से संयोजित उत्पादन क्षमताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा तय किए गए अन्य संव्यवहारों की संविदागत क्षमताओं का योग होगा।

पूर्व वित्तीय वर्ष में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता अनुज्ञप्तिधारी के लिए वितरित भार का योग होगी।

(ख) असंकुलित पारेषण कारीडोर की दशा में अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता द्वारा संदेय पारेषण प्रभार निम्नानुसार उद्गृहीत किए जाएंगे, अर्थात् :-

- (1) एक ब्लॉक में एक दिन में 6 घंटे तक : एसटी रेट का 1/4वां
- (2) घंटे से अधिक तथा एक ब्लॉक में दिन में 12 घंटे तक : एसटी रेट का 1/2
- (3) घंटे से अधिक और एक ब्लॉक में दिन में 24 घंटे : एसटी दर के बराबर।

(ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रति मेगावाट प्रतिदिन रुपए में दर की घोषणा करेगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियत रहेगी :

परंतु यह कि जहां क्षमता का आरक्षण विनियम 6 में विनिर्दिष्ट रीति में बोली के परिणामस्वरूप किया गया हो, वहां एसटी दर बोली के लिए न्यूनतम कीमत के रूप में की जाएगी।

- (iii) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं से संगृहीत प्रभारों का 25% निर्बाध पहुंच (इलेक्ट्रिकल लाइन) प्रदाता द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा तथा 75% का समायोजन अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं (इलेक्ट्रिकल लाइन) द्वारा संदेय प्रभारों में कटौती के मद्दे किया जाएगा।

- (iv) अंतर्वर्ती पारेषण सुविधाओं का उपयोग प्रदान करने के लिए दरों, प्रभारों तथा निबंधन तथा शर्तों का विनिश्चय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आपस में किया जाएगा :

अधिशेष उपलब्ध क्षमता के परिमाण में किसी विवाद या दरों, प्रभारों और निबंधनों तथा शर्तों पर असहमति का न्यायनिर्णयन आयोग द्वारा किया जाएगा। तथापि, दरों, प्रभारों तथा निबंधन तथा शर्तें उचित तथा युक्तियुक्त होंगी तथा ऐसी प्रसुविधाओं के उपयोग में अनुपात में आबंटित की जा सकेंगी।

(ii) प्रति-सहायिकी अधिभार

पारेषण प्रभारों तथा चक्रण प्रभारों के अतिरिक्त, पारेषण प्रणाली या वितरण नेटवर्क के लिए निर्बाध पहुंच लेने वाले उपभोक्ता प्रति-सहायिकी अधिभार का संदाय करेंगे।

ऐसे निर्बाध पहुंच उपयोक्ता, जो अपने कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों से अपने स्वयं के उपयोग के स्थान तक ऊर्जा अंतरण की निर्बाध पहुंच सुविधा प्रदान कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रति-सहायिकी अधिभार का संदाय करेंगे जैसा अधिनियम द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा के अधीन राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति के अनुसार अवधारित किया जाए।

अधिभार की रकम की संगणना उस प्रवर्ग के उपयोक्ताओं से प्रति-सहायिकी के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए की जाएगी तथा प्रदाय के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त की जाएगी जहां उपयोक्ता अवस्थित है। यदि इस प्रकार संगणित अधिकार नकारात्मक है तो इसे शून्य समझा जाएगा।

(iii) अतिरिक्त अधिभार

- (क) निर्बाध पहुंच प्राप्त करने वाला तथा प्रदाय के अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न व्यक्ति से विद्युत का प्रदाय प्राप्त करने वाला उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त प्रभार का संदाय करेगा जो अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित प्रदाय के लिए उसकी बाध्यताओं से उद्भूत ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की नियत लागत को पूरा करेगा।

- (ख) प्रदाय करने की बाध्यता के लिए अतिरिक्त अधिभार केवल तब संदेय हो जाएंगे यदि निश्चायक रूप से यह दर्शित किया है कि विद्यमान ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता निरंतर उत्कूलित हो गई है या ऐसी संविदा के परिणामस्वरूप नियत लागत का वहन करने के लिए अपरिहार्य बाध्यता तथा भार है।

- (ग) ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जिसका उपभोक्ता निर्बाध पहुंच लेने के लिए आशयित है, आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा संदत्त नियत लागत के लेखा को प्रस्तुत करेगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय की अपनी बाध्यता के लिए उपगत कर रहा है और उत्कूलित हो गई नियत लागत के किसी भी भाग को दर्शित करता है।
- (घ) आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के विवरणों की संवीक्षा करेगा तथा उपभोक्ता की आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगा और उपभोक्ता को संदेय अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो, की रकम का अवधारण करेगा।
- (ङ) अतिरिक्त अधिभार आयोग द्वारा यथा अवधारित सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दायी होंगे।

(iv) अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार

- (क) दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र को संदेय अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार वैसे होंगे जैसा आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अधीन यथा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाए।
- (ख) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए 1000/-रुपए की अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार राज्य भार प्रेषण केंद्र को संदत्त किए जाएंगे।
- (ग) उपरोक्त उप-विनियम (ख) के अनुसार राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा संगृहीत अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवधारित प्रभार के अतिरिक्त होंगे। तथापि, इन्हें राज्य भार प्रेषण केंद्र के पश्चातवर्ती एआरआर में समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार प्रदायकर्ता द्वारा तथा इन विनियमों के अधीन निर्बाध पहुंच प्राप्ति करने वाले उसके उपभोक्ता द्वारा संदेय होंगे।

(v) रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का संदाय लागू स्कीम के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(vi) अन्य प्रभार

खंड (i) से (v) तक के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, किन्हीं ऐसे अन्य प्रभारों, जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, का संदाय निर्बाध पहुंच उपयोक्ता द्वारा किया जाएगा।

17. अननुसूचित विनियम प्रभार तथा अंतःराज्यिक उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी)

अंतःराज्यिक एबीटी के अधीन अननुसूचित विनियम प्रभारों (यूआई प्रभारों) का वाणिज्यिक निपटान निम्नलिखित परिवर्धन/फेरफारों के साथ अंतर-राज्यिक संव्यवहारों को लागू रीति से किया जाएगा :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अधीन, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र अपने स्वयं के उपयोग के स्थान तक अपने उत्पादन को ले जाने के लिए प्रति-सहायिकी अधिभार का संदाय किए बिना निर्बाध के लिए हकदार हैं। इसके अतिरिक्त :

- (i) 15 मेगावाट तक की कुल उत्पादन क्षमता वाले उत्पादन केंद्र यूआई प्रणाली के अधीन प्रचालित हो सकेंगे तथा राज्य पूल में ऊर्जा को अंतःक्षेपण कर सकेंगे और राज्य पूल खाते से यूआई दर पर ग्रिड में उत्पादन के ऐसे अंतःक्षेपण के लिए संदाय करेंगे।
- (ii) तथापि, 15 मेगावाट से ऊपर के कुल क्षमता वाले उत्पादन केंद्रों को गोमिंग से बचने के लिए केंविविआ द्वारा अनुबद्ध प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा :

(क) 15 मिनट के किसी भी समय ब्लॉक में घोषित क्षमता का 105% किसी उत्पादन तथा संपूर्ण दिन घोषित औसत क्षमता का 101% तक की संकलित औसत को गोमिंग नहीं माना जाएगा, तथा उत्पादक घोषित क्षमता अनुसूचित उत्पादन से घोषित क्षमता से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यूआई प्रभारों का हकदार होगा।

(ख) विहित सीमाओं से परे किसी उत्पादन के लिए, राज्य भार प्रेषण केंद्र जांच करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई गोमिंग नहीं है तथा, यदि राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा गोमिंग पाई जाती है, तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केंद्र को शोध तत्स्थानी यूआई प्रभारों में शून्य तक कमी की जाएगी तथा उस रकम को फायदाग्राहियों के यूआई खाते में उत्पादन केंद्र में उसकी क्षमता हिस्सेदारी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा।

- (iii) निर्बाध पहुंच का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता को वितरण अनज्ञप्तिधारी के समकक्ष प्रवर्ग में सामान्य उपभोक्ता को लागू नियमों के अनुसार निरंतर माना जाने वाला समझा जाएगा। अतः, उसे उसकी अनुसूचित निकासी से अंतर करने के लिए दंडित किया जाएगा जो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी या ग्रिड की वोल्टता के रूप में ग्रिड के लिए अहितकर हो सकेगा। इसी समय

यदि वह ग्रिड के लिए सहायक होता है तो वह अपनी अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रकार के यूआई प्रभारों का संदाय नहीं करेगा।

18. प्रतिभूति निक्षेप तथा अन्य वाणिज्यिक शर्तें

- (i) 3 मास से अधिक के निर्बाध पहुंच के लिए प्रभारों के मद्दे संदाय समिति के रूप में, तय संविदा मांग या अनुसूचित निकासी के आधार पर औसत बिलिंग को 3 मास के बराबर निक्षेप राज्य पारेषण उपयोगिताओं के साथ बनाए रखा जाएगा।
- (ii) 3 मास से अधिक के निर्बाध पहुंच के लिए एसएलडीसी प्रभारों के मद्दे संदाय प्रतिभूति के रूप में, एसएलडीसी प्रभारों के 3 मास के बराबर निक्षेप राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ बनाए रखा जाएगा।
- (iii) चक्रण प्रभार, अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार के मद्दे तीन मास से अधिक के निर्बाध पहुंच के लिए संदाय प्रतिभूति के रूप में, इन प्रभारों के लिए औसत बिलिंग के 3 मास के बराबर निक्षेप को प्रदाय के क्षेत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ बनाए रखा जाएगा :

परंतु यह कि 3 मास से कम निर्बाध पहुंच के लिए, संदाय प्रतिभूति इस विनियम के उप-विनियम (i), (ii) तथा (iv) में यथा उल्लिखित प्रभारों से संबंधित निर्बाध पहुंच की अवधि के लिए अग्रिम संदाय किया जाएगा।

- (iv) ऐसी प्रतिभूति नकद जमा के रूप में, प्रत्ययपत्र आदि के रूप में हो सकेगी। तथापि, 3 मास से कम निर्बाध पहुंच के लिए ऐसी प्रतिभूति नकद निक्षेप के रूप में ही होगी।
- (v) पारेषण तथा चक्रण प्रभारों तथा अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभारों जैसे संदाय निबंधन, उधार पात्रता; क्षतिपूरण और अपरिहार्य घटनाओं की स्थिति, के लिए अन्य वाणिज्यिक शर्तों को दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता तथा अल्प-कालिक उपयोक्ता के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा 60 दिन के भीतर मानकीकृत किया जाएगा।

19. ऊर्जा हानियां

निर्बाध पहुंच उपयोक्ता अपनी निकासी के अनुपात में आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पारेषण प्रणाली तथा वितरण नेटवर्क में औसत हानियों का वहन करेगा। पारेषण प्रणाली तथा वितरण नेटवर्क में हानि की प्रतिपूर्ति अंतःक्षेपण स्थान (नों) पर अतिरिक्त अंतःक्षेपण द्वारा की जाएगी।

20. विशेष ऊर्जा मीटर

- (i) निर्बाध पहुंच उपयोक्ता सक्रिय ऊर्जा के समय मापमान में अंतर करने में समर्थ मुख्य मीटर तथा सक्रिय ऊर्जा का वोल्टता अंतर करने वाले माप के रूप में एबीटी के अनुरूप ऐसे विशेष ऊर्जा मीटर प्रदान करेगा जैसा राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए जो वोल्टता, प्रदाय का स्थान तथा अवधि और टैरिफ प्रवर्ग के आधार पर ऐसे मीटरिंग कोड के अनुसार होगा जैसा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ii) मुख्य मीटरों को हमेशा बेहतर स्थिति में बनाए रखा जाएगा तथा वे नोडल अभिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुल रहेंगे।
- (iii) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी मुख्य मीटरों के रूप में उसी विनिर्देशनों के जांच मीटर प्रदान करेगा।
- (iv) मुख्य तथा जांच मीटरों की अंतर्वलित अन्य पक्षकार की उपस्थिति में संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवधिक रूप से जांच तथा अंशशोधित किया जाएगा। मुख्य तथा जांचे गए मीटरों को दोनों पक्षकारों द्वारा सीलबंद किया जाएगा। खराब मीटरों को तुरंत बदला जाएगा।
- (v) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी, उत्पादक तथा निर्बाध पहुंच उपयोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा नियत दिन तथा घंटों पर मुख्य तथा जांचे गए मीटरों की रीडिंग आवधिक रूप से की जाएगी, मीटर रीडिंग के संबंध में संसूचना मीटर रीडिंग के 12 घंटे के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, एसएलडीसी, निर्बाध पहुंच उपयोक्ता तथा उत्पादन कंपनी या व्यापारी को दी जाएगी।
- (vi) जब मुख्य मीटरों को खराब या बंद पड़ा हुआ पाया जाता है तब जांच मीटरों की रीडिंग पर विचार किया जाएगा यदि मुख्य तथा जांच मीटरों की रीडिंग के बीच अंतर पाया जाता है अर्थात् मुख्य मीटर की रीडिंग सुसंगतता शुद्धता वर्ग के लिए अनुज्ञेय त्रुटियों की प्रतिशतता दोगुना से अधिक होती है। खराब पाए गए मीटर को तत्काल बदला जाएगा।
- (vii) परीक्षण जांचों या अन्यथा दोनों के दौरान यदि मुख्य मीटर तथा तत्स्थानी जांच मीटर आईएस विनिर्देशनों के अनुसार त्रुटि की अनुज्ञेय सीमाओं से परे पाए जाते हैं तो दोनों मीटरों को तत्काल अंशशोधित किया जाएगा तथा संशोधन ऐसे परीक्षण जांच के समय तक मास की अवधि के लिए बिलिंग प्रयोजनों के लिए ऊर्जा के ठीक उत्पादन के लिए मुख्य मीटर द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऊर्जा के उत्पादन को लागू होंगे। अगली मासिक मीटर रीडिंग तक तत्पश्चात्, अवधि के लिए बिलिंग अंशशोधित मुख्य मीटरों के अनुसार होगी।

(viii) यदि निर्बाध पहुंच उपयोक्ता अनुज्ञप्तिधारी से मुख्य मीटर प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति देंगे तथा उसको किराया का संदाय करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटरों को बनाए रखा जाएगा।

21. निर्बाध पहुंच के आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा

निर्बाध पहुंच प्रदान करने के आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए नोडल अभिकरण द्वारा, यथासाध्य, निम्नलिखित समय-अनुसूची का पालन किया जाएगा :

1. अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच

एक सप्ताह तक -- 2 दिन
एक सप्ताह से अधिक -- 3 दिन

2. दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच

प्रणाली सुदृढीकरण के बिना पहुंच की संभाव्यता के बारे में सूचना - 30 दिन

लागत प्राक्कलन तथा समापन अनुसूची के साथ प्रणाली सुदृढीकरण अध्ययन के परिणामस्वरूप संसूचना - 90 दिन

22. कटौती पूर्विकता

जब पारेषण या वितरण क्षमता अवरोधों या अन्यथा के कारण, पहले ही अनुदत्त निर्बाध पहुंच में कटौती करना आवश्यक हो गया है तो अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता पहले कटौती करेंगे तथा उसके बाद कटौती दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता करेंगे :

परंतु यह कि प्रवर्ग के भीतर, सभी उपयोक्ताओं की वही कटौती पूर्विकता होगी तथा दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं की दशा में आबंटित क्षमता तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं की दशा में आरक्षित क्षमता में अनुपातिक कटौती करेंगे।

23. राज्य ग्रिड संहिता का अनुपालन

निर्बाध पहुंच उपयोक्ता, यथा लागू राज्य ग्रिड संहिता तथा समय-समय पर राज्य पारेषण/उपयागिता तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करेंगे।

24. प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण

- (क) उपभोक्ता को निर्बाध पहुंच की दशा में, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी (या संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यदि उपभोक्ता अपने नेटवर्क से सीधे जुड़ा हो) विनियम 15 में यथा उल्लिखित निर्बाध पहुंच प्रभारों (जैसे यथास्थिति पारेषण प्रभारों/चक्रण प्रभारों/प्रति सहायिकी अधिभार/अतिरिक्त अधिभार) की बाबत उपभोक्ता को बताएगा तथा निर्बाध पहुंच उपयोक्ता उन प्रभारों का संदाय अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोक्ता के बीच थोक क्षमता करार में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार करेगा :

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित निर्बाध पहुंच प्रभारों पर आर्डर देने के लिए समुचित बैक-टू-बैक व्यवस्था करनी होगी।

- (ख) निर्बाध पहुंच की बाबत अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र को संदत्त किए जाएंगे।
- (ग) अननुसूचित विनियम प्रभार साप्ताहिक आधार पर ऐसी रीति से संदत्त किए जाएंगे जैसा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निदेश दिया जाए।

25. निर्बाध पहुंच की फेजिंग

- (i) विद्युत के प्रदाय, जहां किसी समय उपलब्ध की जाने वाली अधिकतम ऊर्जा अधिनियम तथा इन विनियमों में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान करने के अधीन रहते हुए 1 मेगावाट से अधिक हो, की अपेक्षा वाले सभी उपभोक्ताओं को फेज 1 में निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की जाएगी;
- (ii) आयोग किसी समय 1 मेगावाट संविदा मांग की अपेक्षा करने वाले उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच अनुज्ञात कर सकेगा जैसा वह प्रचालनात्मक अवरोधों, अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा फेज 1 में निर्बाध पहुंच के प्रचालन के आधार पर साध्य समझे।

26. सूचना प्रणाली

राज्य भार प्रेषण केंद्र अपनी वेबसाइट पर पृथक् “ निर्बाध पहुंच जानकारी ” नामक वेबपृष्ठ पर निम्नलिखित जानकारी डालेगा :

- (i) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं (एसटी, रेट) के लिए प्रतिदिन प्रति मेगावाट रूप में न्यूनतम दर।

(ii) वर्तमान अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ता संबंधी प्रास्थिति रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :-

- (क) निर्बाध पहुंच उपयोक्ता का नाम;
- (ख) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख);
- (ग) अंतःक्षेपण का स्थान;
- (घ) निकासी का स्थान;
- (ङ) प्रयुक्त पारेषण/वितरण प्रणाली (क्षेत्र तथा स्वामित्व के अनुसार);
- (च) आरक्षित क्षमता; और
- (छ) लागू दर (प्रतिदिन प्रति मेगावाट रुपए)।

टिप्पण : प्रास्थिति में कोई भी परिवर्तन होने पर प्रास्थिति रिपोर्ट को अद्यतन किया जाएगा।

(iii) पिछली अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं संबंधी मासिक-वार तथा वर्ष-वार रिपोर्ट, जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :

- (क) निर्बाध पहुंच उपयोक्ता का नाम;
- (ख) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख);
- (ग) अंतःक्षेपण का स्थान;
- (घ) निकासी का स्थान;
- (ङ) प्रयुक्त पारेषण/वितरण प्रणाली;
- (च) आरक्षित क्षमता;
- (छ) लागू दर (प्रतिदिन प्रति मेगावाट रुपए); और
- (ज) वास्तविक भार कारक

टिप्पण : सभी पूर्व रिपोर्ट वेब-अभिलेखागार में भी उपलब्ध होंगी।

(iv) विभिन्न राज्य अनुज्ञप्तिधारियों के बीच लिंकों के उपयोग के बारे में जानकारी जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :

- (क) अद्यतन करने का समय;
- (ख) लिंक का नाम;
- (ग) लिंक की कुल क्षमता;
- (घ) प्रयुक्त अनुसूचित क्षमता (निर्बाध पहुंच का उपयोग-वार ब्यौरा देते हुए); और
- (ङ) प्रयुक्त लिंक की वर्तमान क्षमता।

टिप्पण : इस जानकारी को कम से कम घंटे के आधार पर अद्यतन किया जाएगा तथा जहां साध्य हो वहां 15 मिनट के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

(v) पिछले 52 सप्ताहों के लिए औसत ऊर्जा हानियों के बारे में जानकारी;

परंतु यह कि वेब आधारित जानकारी प्रणाली का प्रकाशन इन विनियमों के लागू होने के 180 दिन के भीतर प्रारंभ होगा। प्रत्येक पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी एसएलडीसी को उपरोक्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

सभी अनुज्ञप्तिधारी 180 दिन के भीतर अपनी प्रणाली का उपयोग करने वाले (जिसमें स्वयं उपयोग तथा ऐसी विभाजित इकाइयों द्वारा उपयोग जो वर्तमान में एकीकृत है या पहले एकीकृत थी) वर्तमान दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच उपयोक्ताओं की, उनके ब्यौरे सहित या तो अपनी वेबसाइट पर या राज्य भार प्रेषण केंद्र की वेबसाइट पर, घोषणा करेंगे।

टिप्पण : प्रास्थिति में कोई भी परिवर्तन होने पर इस सूची को अद्यतन किया जाएगा।

27. संसूचना सुविधा

निर्बाध पहुंच उपयोक्ता ऐसी संसूचना अपेक्षाओं को पूरा करेंगे जैसा नोडल अभिकरण समय-समय पर निदेश दे।

28. प्रतितोष तंत्र

- (i) निर्बाध पहुंच से संबंधित सभी विवाद तथा शिकायतें राज्य भार प्रेषण केंद्र को की जाएंगी जो तीस दिन के भीतर शिकायतों का अन्वेषण करने तथा उनका समाधान करने का प्रयास करेगा।
- (ii) जहां राज्य भार प्रेषण केंद्र शिकायतों का समाधान करने में असमर्थ है वहां राज्य ग्रिड संहिता के अधीन गठित राज्य ग्रिड संहिता पुनर्विलोकन समिति, तीस दिन के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगी;
- (iii) जहां राज्य ग्रिड संहिता पुनर्विलोकन समिति गठित नहीं की गई है या उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का समाधान करने में असमर्थ है, शिकायत को आयोग को भेजा जाएगा; और
- (iv) इन विनियमों के अधीन प्रक्रियाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा आवेदन प्ररूपों को विरचित करने के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्रों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का समन्वय राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा किया जाएगा।

29. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य पारेषण उपयोगिता, राज्य भार प्रेषण केंद्र, अनुज्ञप्तिधारियों तथा निर्बाध पहुंच उपयोक्ता को ऐसी कार्रवाई करने का आदेश दे सकेगा जिसे कठिनाई को दूर करने के लिए आयोग आवश्यक या समीचीन समझे।

30. निर्बाध पहुंच का प्रचालनीकरण

भार प्रेषण केंद्रों से निर्बाध पहुंच के लिए एबीटी शिकायत मीटिंग प्रणाली लगाने तथा एसएलडीसी द्वारा ऊर्जा लेखांकन तथा वाणिज्यिक व्यवस्थापन के लिए प्रक्रिया तैयार करने की अपेक्षा की जाएगी।

जे. एस. सहरावत, सचिव

[विज्ञापन III/4/218-I/09-असा.]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 11th February, 2010

No. JERC-9/2009.—In exercise of the powers conferred on it by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all the powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and the Union Territories, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely :-

1. Short Title, Commencement and Extent

- (i) These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Open Access in Transmission and Distribution) Regulations, 2009.
- (ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (iii) These regulations extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

- (b) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and the Union Territories;
- (c) "existing beneficiary" means a person who is a user of the transmission system or distribution network on the date of commencement of these regulations either as a generating company or as a transmission licensee or distribution licensee;
- (d) "nodal agency" means the nodal agency defined in Regulation 8 of these regulations;
- (e) "open access user" means a person permitted to use intra-State transmission system or receive supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply, and the expression includes a generating company and a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;
- (f) "State" means the State of Goa, and includes a Union Territory, but does not include the Union Territory of Delhi.

- (2) Words and expressions occurring in these regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meanings as respectively assigned to them in the Act and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the Act shall have the meanings generally assigned to them in the electricity industry.

3. Categorization of Open Access Users

- (i) The open access users shall be divided into two categories, namely: -

- (a) Long-term open access users, and
- (b) Short-term open access users.

- (ii) The persons availing or intending to avail open access for a period of twenty-five years or more shall be the long-term open access users:

Provided that the existing beneficiaries shall be deemed to be the long-term open access users of the transmission system or the distribution network, as the case may be.

- (iii) The open access users other than the long-term open access users shall be the short-term open access users:

Provided that the maximum duration for the short-term open access allowed at a time shall not exceed one year:

Provided further that the short-term open access users shall be eligible and re-eligible to obtain fresh reservation after expiry of their term.

4. Publication of Details of Existing Beneficiaries

The transmission /distribution licensees shall publish the details of the existing beneficiaries (including self-use and use by unbundled agencies which were previously integrated) either on their own website or on the website of the State Load Dispatch Centre within 180 days from the date of commencement of these regulations.

5. Criteria for Long-term and Short-term Open Access

- (i) Long-term open access shall be allowed in accordance with the transmission planning criterion stipulated in the State Grid Code.
- (ii) Short-term open access shall be allowed, if the request for open access can be accommodated by utilizing: -
 - a) Inherent design margins
 - b) Margins available due to variation in power flows; and
 - c) Margins available due to in-built spare transmission capacity created to cater to future load growth.

6. Future Requests for Open Access

All future requests for use of the transmission system and distribution network shall be handled in accordance with these regulations.

7. Allotment Priority of Long-term Open Access User

Allotment priority of a long-term open access user shall be higher than reservation priority of a short-term open access user:

Provided that within a category (long-term open access users or short-term open access users), there shall be no discrimination between open access users and self-use by an integrated entity.

8. Nodal Agency

- (i) The nodal agency for arranging the long-term open access within the State shall be the State Transmission Utility (STU).
- (ii) The nodal agency for the short-term open access within the State shall be the State Load Dispatch Centre (SLDC).

9. Detailed Procedure

The nodal agency shall issue detailed procedure, guidelines, and the form of application within 30 days from the date of commencement of these regulations.

10. Procedure for Long-Term Open Access

- (i) An application for long-term open access shall be submitted to the concerned nodal agency in accordance with the detailed procedure issued under Regulation 9.
- (ii) The application shall contain the details, such as capacity needed, point(s) of injection, point(s) of drawal, duration of availing open access, peak load, average load and such other additional information that may be specified by the nodal agency:
- (iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rs fifty thousand payable in the name and in the manner to be decided by the nodal agency;
- (iv) Based on system studies conducted by the nodal agency in consultation with other agencies concerned, including other transmission and distribution licensees, the nodal agency shall, within 30 days of receipt of the application, intimate to the applicant whether or not the long-term open access can be allowed without further system strengthening:

Provided that where the long-term open access can be allowed without further system strengthening, this shall be allowed immediately after entering into commercial agreements.

- (v) If, in the opinion of the nodal agency, further system strengthening is essential before providing the long-term access, the applicant may request the nodal agency to carry out the system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening;
- (vi) The nodal agency shall carry out the studies immediately on receipt of request from the applicant under sub-regulation (v) and intimate results of the studies to the applicant within 90 days of receipt of request .
- (vii) The applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the nodal agency for carrying out the system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening:

Provided that the fee of Rupees fifty thousand paid by the applicant shall be adjusted against the actual expenditure to be reimbursed by the applicant.

11. Bulk Capacity Agreement

- (i) A long-term open access user shall enter into Bulk Power Transmission / Distribution Capacity Agreement with the transmission / distribution licensee for use of their transmission system and distribution network.
- (ii) The agreement shall provide, amongst other things for the eventuality of premature its termination and its consequences on the contracting parties.
- (iii) After agreement has been entered into and copies furnished to State Load Dispatch Centre, the State Load Dispatch Centre shall inform the open access user the date from which open access is likely to be available:

Provided that the date of availability of open access shall not be later than 3 days from the date of furnishing of agreements.

12. Exit Option

- (i) A long-term open access user shall not relinquish or transfer his rights and obligations under the Bulk Power Transmission / Distribution Capacity Agreement, without prior approval of the Commission.
- (ii) The relinquishment or transfer of rights and obligations by a long-term open access user shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

13. Procedure for Short-Term Open Access

- (i) A short-term open access user shall submit an application for transmission/distribution access to the State Load Dispatch Centre.
- (ii) The application shall contain the details such as capacity needed, point(s) of injection, point(s) of drawal, duration of availing open access, peak load, average load and such other additional information that may be specified by the State Load Dispatch Centre;
- (iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rupees five thousand payable in the name and in the manner to be decided by the State Load Dispatch Centre;
- (iv) The reserved capacity shall not be transferred by a short-term open access user to any other person.

14. Reservation of Capacity for Short-term Users

- (i) In case of short-term open access users, at given point of time, if the capacity sought to be reserved is less than the available capacity, each short-term open access user shall pay the transmission or wheeling charges in accordance with Regulation 16.
- (ii) In case of short-term open access, if the capacity sought to be reserved by the open access users is more than the available capacity at that point of time, reservation of capacity shall be considered in accordance with the following procedure, namely –
 - (a) The State Load Dispatch Centre concerned shall invite snap bids through fax/e-mail.
 - (b) The floor price for the bidding shall be the price determined in accordance with Regulation 16.
 - (c) The bidders shall quote price in terms of percentage points above the floor price.
 - (d) The reservation of capacity shall be made in decreasing order of the price quoted.

- (e) In case of equal price, if required (e.g., due to capacity being short), the reservation of capacity shall be made *pro rata* to the capacity sought.
- (f) The open access user getting reservation for a capacity less than the capacity sought by him shall pay charges for the capacity allotted at the rate quoted by him.
- (g) The State Load Dispatch Centre shall, within 45 days, formulate a detailed procedure for reservation of transmission and distribution capacity to short-term open access users, including the detailed procedure for bidding.

15. Non-Utilization of Reserved Capacity by Short-Term Open Access User

- (i) In case a short-term open access user is unable to utilize, full or substantial part of the reserved capacity, he shall inform the State Load Dispatch Centre along with reasons for his inability to utilize the reserved capacity and may surrender the reserved capacity;
- (ii) The State Load Dispatch Centre may reduce or cancel the reserved capacity of a short-term open access user when such a short-term open access user frequently under-utilizes the reserved capacity;
- (iii) The short-term open access user, who has surrendered the reserved capacity under sub-regulation (i) or whose reserved capacity has been reduced or cancelled under sub-regulation (ii), shall bear the transmission / wheeling charges and the scheduling and system operation charge based on the original reserved transmission capacity for seven days or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever period is shorter.
- (iv) The capacity available as a result of surrender or reduction or cancellation of the reserved capacity by the State Load Dispatch Centre under sub-regulation (i) or sub-regulation (ii), may be reserved for any other short-term open access user in accordance with these regulations.

16. Open Access Charges

The charges for open access shall consist of one or more of the following components, namely:-

(i) Transmission / Distribution (Wheeling) Charges

The charges for use of the system of the licensee for intra-State transmission or distribution except intervening transmission facilities shall be regulated as under, namely:-

- (i) The annual charges shall be determined by the Commission in accordance with the terms and conditions of tariff notified by the Commission from time to time and after deducting the adjustable revenue from the short-term

open access users, these charges shall be shared by the long-term open access users;

- (ii) (a) The charges payable by a short-term open access user shall be calculated in accordance with the following methodology:

$$\text{ST RATE} = 0.25 \times [\text{TSC} / \text{Av CAP}] / 365$$

Where:

ST RATE is the rate for short-term open access user in Rs per MW per day.

"TSC" means the Annual Transmission / Distribution Charges of the transmission or distribution licensee for the immediately preceding financial year.

"Av CAP" means the average capacity in MW served by the system

The capacity of the transmission licensee in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other transactions handled by the system of the transmission licensee.

The capacity of the distribution licensee in the previous financial year shall be the sum of the distributed load for the licensee.

- (b) The transmission charges payable by a short-term open access user in case of un-congested transmission corridor shall be levied as under, namely:-

- (1) Up to 6 hours in a day in one block: 1/4th of ST RATE
- (2) More than 6 hours and up to 12 hours in a day in one block: ½ of ST RATE
- (3) More than 12 hours and upto 24 hours in a day in one block: equal to ST RATE

- (c) Every licensee shall declare rate in Rs per MW per day, which shall remain fixed for a period of one year:

Provided that where reservation of capacity has been done consequent to bidding in the manner specified in Regulation 6, the ST RATE shall be taken as the floor price for bidding.

- (iii) 25% of the charges collected from the short-term open access users shall be retained by the open access providers (electrical lines) and the balance 75% shall be adjusted towards reduction in the charges payable by the long-term open access users (electrical lines).
- (iv) The rates, charges and terms and conditions for providing the use of intervening transmission facilities may be mutually decided by the licensees:

Provided that any dispute on the extent of surplus capacity available or disagreement on the rates, charges and terms and conditions, shall be adjudicated upon by the Commission. However the rates, charges and terms and conditions shall be fair and reasonable and may be allocated in proportion to the use of such facilities.

(ii) Cross-Subsidy Surcharge

In addition to transmission charges and wheeling charges, a consumer availing open access to the transmission system or the distribution network shall pay the cross-subsidy surcharge.

The open access users, except those availing open access facility to transfer power from their captive generating plants to the destination of their own use, shall pay the cross-subsidy surcharge to the distribution licensee of their area, as determined by the Commission from time to time under sub-section (2) of Section 42 of the Act, in accordance with the National Electricity Policy and Tariff Policy.

The amount of surcharge shall be so calculated as to meet the current level of cross-subsidy from that category of consumers and shall be paid to the distribution licensee of area of supply where the consumer is located. In case surcharge so calculated is negative, it shall be treated as nil.

(iii) Additional Surcharge

- (a) A consumer availing open access and receiving supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply shall pay to the distribution licensee an additional surcharge, in addition to wheeling charges and cross-subsidy surcharge, to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply as provided under sub-section (4) of section 42 of the Act.
- (b) The additional surcharge for obligation to supply shall become payable only if it is conclusively demonstrated that the obligation of a licensee, in terms of existing power purchase commitments, has been and continues to be stranded, or there is an unavoidable obligation and incidence to bear fixed costs consequent to such contract.
- (c) The distribution licensee whose consumer intends to avail open access shall submit to the Commission within thirty days of receipt of application an account of fixed cost paid by such open access user which the licensee is incurring towards his obligation to supply and demonstrate if any part of the fixed cost has become stranded.
- (d) The Commission shall scrutinize the statement of accounts submitted by the licensee and obtain objections, if any, of the consumer and determine the amount of additional surcharge, if any, payable by the consumer.

- (e) The additional surcharge shall be liable for such period not normally exceeding one year as the Commission may determine.

(iv) Scheduling and System Operation Charges

- (a) The scheduling and system operation charges payable to State Load Dispatch Centre by long-term open access users shall be same as determined by the Commission in accordance with the Regulations that may be notified by it under Section 32 of the Act.
- (b) The scheduling and system operation charges of Rs.1000/-per day or part of the day shall be paid by a short-term open access user to State Load Dispatch Centre
- (c) The scheduling and system operation charges collected by the State Load Dispatch Centre in accordance with sub-regulation (b) above shall be in addition to charges determined by the Commission under Section 32 of the Act. These will be however adjusted in the subsequent ARR of SLDC.

Explanation

Scheduling and system operation charges shall be payable by a supplier as well as his consumer availing open access under these Regulations.

(v) Reactive Energy Charges

The payment for the reactive energy charges for the open access user shall be calculated in accordance with the scheme applicable.

(vi) Other Charges

In addition to the charges specified under clauses (i) to (v), any other charges as may be specified by the Commission from time to time shall be payable by the open access user.

17. Unscheduled Interchange Charges under Intra-State Availability Based Tariff (ABT)

The commercial settlement of Unscheduled Interchange charges (UI charges) under intra- State ABT shall be in the manner applicable for Inter-State transactions with the following additions/variations:-

Under section 9 of Electricity Act, 2003, Captive power plants are entitled for open access without payment of cross-subsidy surcharge, to carry their generation to the point of their own use. In addition to this:

- (i) A generating station with a total capacity of generation up to 15 MW may operate under UI regime and inject power into the state pool and will be paid for such injection of generation into grid at the UI rate from the state pool account.
- (ii) However the generating stations with a total capacity above 15 MW shall be regulated as follows according to CERC stipulations to avoid gaming:

- (a) Any generation up to 105% of the declared capacity in any time block of 15 minutes and aggregated averaging up to 101% of the average declared capacity over a day shall not be construed as gaming, and the generator shall be entitled to UI charges for such excess generation above the declared capacity scheduled generation (SG).
- (b) For any generation beyond the prescribed limits, the State Load Dispatch Centre shall investigate so as to ensure that there is no gaming, and if gaming is found by the State Load Dispatch Centre, the corresponding UI charges due to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station.
- (iii) A consumer opting for open access shall continue to be treated according to the rules applicable to a normal consumer in the equivalent category of the distribution licensee. Thus he will be penalized for deviating from his scheduled drawal which may be detrimental to the grid either by way of frequency or voltage of the grid. At the same time he will not be paid any UI charges for changing his schedule even if it be helpful to the grid.

18. Security Deposit and Other Commercial Conditions

- (i) As a payment security towards charges for open access of more than 3 months, a deposit equal to 3 months of the average billing on the basis of agreed contract demand or scheduled drawal shall be maintained with the State Transmission Utility.
- (ii) As a payment security towards SLDC charges for open access of more than 3 months, a deposit equal to 3 months of the SLDC charges shall be maintained with the State Load Dispatch Centre.
- (iii) As a payment security for open access of more than 3 months towards wheeling charges, surcharge and additional surcharge, a deposit equal to 3 months of average billing for these charges shall be maintained with the distribution licensee of the area of supply.

Provided that for open access less than 3 months, payment security shall be advance payment for the duration of the open access pertaining to the charges as mentioned in this Regulation in sub-regulation (i), (ii) and (iv).

- (iv) Such security could be in form of cash deposit, letter of credit etc. However for open access less than 3 months, such security shall be only in form of cash deposit.
- (v) Other commercial conditions for transmission & wheeling charges and scheduling and system operation charges, such as, terms of payment, creditworthiness, indemnification, and force majeure conditions shall be standardized within 60 days by the State Transmission Utility for long-term open access user and by the State Load Dispatch Centre for the short-term open access users.

19. Energy losses

The open access user shall bear average energy losses in the transmission system and distribution network as specified by the Commission in proportionate to its drawal. The loss in the transmission system and distribution network shall be compensated by additional injection at the injection point(s).

20. Special Energy Meters

- (i) The open access user shall provide ABT compatible Special Energy Meter as Main Meter capable of time differentiated measurements (15 minutes) of active energy and voltage differentiated measurement of reactive energy as may be specified by the State Transmission Utility or the State Load Dispatch Centre which shall be according to the Metering Code as may be specified by Central Electricity Authority based on voltage, point and period of supply and tariff category.
- (ii) Main meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorized by the nodal agency.
- (iii) The concerned licensee may provide check meters of the same specifications as main meters.
- (iv) The main and check meters shall be periodically tested and calibrated by the concerned licensee in the presence of other party involved. Main and check meters shall be sealed by both parties. Defective meter shall be replaced immediately.
- (v) Reading of main and check meters shall be taken periodically at appointed day and hour by authorized officer of the concerned licensee, the generator and the open access user or his representative, as the case may be. Meter reading shall be communicated to SLDC, the open access user and the generating company or trader, as the case may be, by the distribution licensee, within 12 hours of meter reading.
- (vi) Readings of the check meters shall be considered when main meters are found to be defective or stopped. Both the main meter and check meter shall be tested for accuracy if difference between the readings of main and check meters vis-à-vis main meter reading exceed twice the percentage errors permissible for relevant accuracy class. The meter found defective shall be replaced immediately.
- (vii) If during the test checks or otherwise, both the main meters and the corresponding check meters are found to be beyond permissible limits of error as per the IS specifications, both the meters shall be immediately calibrated and the correction applied to the generation of energy registered by the main meter to arrive at the correct generation of energy registered by

the main meter to arrive at the correct generation of energy for billing purposes for the period of the month up to the time of such test check. Billing for the period thereafter until the next monthly meter reading shall be as per the calibrated main meter.

- (viii) If an open access user requires the licensee to provide main meter it shall provide security to the licensee and shall pay for its rent. The meter shall be maintained by the licensee.

21. Time-schedule for Processing Application For Open Access

As far as practicable, the following time schedule shall be adhered to by the nodal agency for processing of the application for grant of open access:

1. Short-term Open Access

Up to one week - 2 days
More than a week - 3 days

2. Long-term Open Access

Intimation regarding feasibility of access without system strengthening - 30 days

Intimation of results of system strengthening studies with cost estimates and completion schedule - 90 days

22. Curtailment Priority

When because of transmission or distribution capacity constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the the open access already granted, the short-term open access users shall be curtailed first, followed by the long-term open access users:

Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and shall be curtailed *pro rata* to the allotted capacity in the case of long term open access users and the reserved capacity in the case of short-term open access users.

23. Compliance of State Grid Code

The open access user shall abide by the State Grid Code, as applicable and instructions given by State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre from time to time.

24. Collection and Disbursement of Charges

- (a) In case of open access to consumer, the concerned distribution licensee (or the concerned transmission licensee if the consumer is directly connected to its network), may invoice a consumer in respect of the open access charges (such as

Transmission Charges/Wheeling Charges/Cross Subsidy Surcharge/ Additional Surcharge, as the case may be) as set out in Regulation 15 and the open access user shall pay those charges, in accordance with the procedures set out in the Bulk Capacity Agreement between the licensees and the user:

Provided that the distribution licensee and transmission licensee shall have appropriate back-to-back arrangements in place in order to pass on Open Access Charges, pertaining to the concerned Licensees.

- (b) The scheduling and system operation charges in respect of open access shall be paid to the State Load Dispatch Centre by the Open Access users.
- (c) The Unscheduled Interchange charges shall be paid in the manner as directed by the State Load Dispatch Centre on weekly basis.

25. Phasing of Open Access

- (i) Open access shall be allowed in the phase I to all consumers requiring a supply of electricity where the maximum power to be made available at any time exceeds 1 MW subject to the satisfaction of the conditions contained in the Act and these regulations:
- (ii) The Commission may allow open access to consumers requiring up to 1 MW contract demand at any time as it may consider feasible having regard to operational constraints, other factors and based on experience of operations of open access in phase I.

26. Information System

The State Load Dispatch Centre shall post following information on their websites in a separate web-page titled "Open access information":

- (i) Floor rate in rupees per MW per day for the short-term open access users (ST_RATE)
- (ii) A status report on the current short-term open access users indicating:-
 - (a) Name of open access user;
 - (b) Period of the access granted (start date and end date);
 - (c) Point(s) of injection;
 - (d) Point(s) of drawal;
 - (e) Transmission / Distribution systems used (in terms of region and ownership);
 - (f) Reserved capacity; and
 - (g) Applicable rate (Rs per MW per day).

Note: The status report shall be updated upon every change in status.

(iii) Month-wise and year-wise report on past short-term open access users indicating:

- (a) Name of the open access user;
- (b) Period of the access granted (start date and end date);
- (c) Point(s) of injection;
- (d) Point(s) of drawal;
- (e) Transmission / Distribution systems used;
- (f) Reserved capacity;
- (g) Applicable rate (Rs per MW per day); and
- (h) Actual load factor.

Note: All previous reports shall also be available in the web-archives.

(iv) Information regarding usage of the links between various State licensees indicating:

- (a) Time of updating;
- (b) Name of the link;
- (c) Total capacity of the link;
- (d) Scheduled capacity use (giving open access user-wise break-up); and
- (e) Current capacity of the link in use.

Note: This information should be updated at least on hourly basis, and wherever feasible on 15 minute basis.

(v) The information regarding average energy losses for the previous 52 weeks:

Provided that publication of web-based information system shall commence within 180 days of coming into force of these Regulations. Each transmission / distribution licensee shall make available the above information to the SLDC.

All licensees shall declare current long-term open access users using their system (including self-use and use by unbundled entities which are presently or were previously integrated) with details thereof either on their own websites or on the website of the State Load Dispatch Centre concerned, within 180 days.

Note: This list shall be updated as and when change in status takes place.

27. Communicating facility

The open access users shall meet the communication requirements as the nodal agency may direct from time to time.

28. Redressal Mechanism

- (i) All disputes and complaints relating to open access shall be made to the State Load Dispatch Centre, which may investigate and endeavor to resolve the grievance within 30 days, and

- (ii) Where State Load Dispatch Center is unable to resolve a grievance, State Grid Code Review Committee constituted under State Grid Code shall endeavor to resolve the grievance within 30 days, and
- (iii) Where State Grid Code Review Committee has not been constituted or is unable to resolve the grievance in the time period specified above, the grievance shall be referred to the Commission.
- (iv) The responsibilities assigned to the State Load Dispatch Centers for formulation of procedures, guidelines and application forms under these regulations shall be coordinated by the State Transmission Utility.

29. Powers to Remove Difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may by general or special order, direct the State Transmission Utility, State Load Dispatch Centre, licensees and the open access user, to take such action, as may appear to the Commission to be necessary or expedient for removing the difficulty.

30. Operationalisation of Open Access

Open access will require installation of ABT compliant metering system by the open access users, Distribution Licensee-wise Area Load Dispatch Centers and procedure for energy accounting and commercial settlement by SLDC.

J. S. SEHRAWAT, Secy.
[ADVT III/4/218-I/09-Exty.]